B.A -3 paper 5

1600-1757 ई० तक ईस्ट इंडिया कम्पनी मूलतः एक व्यापारिक संघ थी। यह व्यापार संघ प्रायः बाहर से बुलियन (सोना, चांदी) लाता था और उसके बदले भारत से विलासिता के उपकरण विदेश ले जाता था। लेकिन, इंग्लैण्ड में भारतीय सामान के आधिक्य से घबड़ाकर ब्रिटिश सरकार को उन दिनों ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे इंग्लैण्ड में भारतीय सामान की बिक्री कठिन हो जाए। "राबिन्सन क्रूसो" नामक उपन्यास के लेखक डेफो ने शिकायत की थी कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों, आलमारियों और सोने के कमरों तक में घुस गया है। 1700 ई० में ब्रिटेन में एक अधिनियम द्वारा एशिया के रेशमी और छपे हुए रंगीन कपड़ों के उपयोग पर रोक लगा दी गई। 1720 ई० में एक कानून द्वारा छींट या रँगे हुए सूती कपड़ों के पहनने या इस्तेमाल करने की मनाही हो गई। 1760 ई० में एक महिला को 200 पौण्ड जुर्माने के रूप में इसलिए देना पड़ा कि उसके पास विदेशी रूमाल था।

इधर भारत में कम्पनी ने जुलाहों पर अत्याचार किया और कम मूल्य पर वस्त्र तैयार करने पर बल दिया। जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कम्पनी ने पेशगी रुपये देने की प्रथा चलायी जिसे **ददनी प्रथा** कहते हैं। इसके अनुसार कम्पनी के कर्मचारी जुलाहों को पेशगी रुपये दे देते थे और बदले में एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि वे एक निश्चित तिथि पर, निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़ा दे देंगे। इस तरह अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर जुलाहों के हजारों परिवारों ने अपना पेशा छोड़ दिया और मजदूरी करना प्रारम्भ कर दिया। भारत की लूट के जरिए ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति के लिए आवश्यक पूँजी का संचय हो गया था। इस तरह ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति आई और इसके फलस्वरूप वहाँ एक शक्तिशाली औद्योगिक वर्ग का जन्म हुआ। इधर भारतीय हस्तशिल्प तेजी से पतनोन्मुख हुआ।

हस्तशिल्प बर्बादी के कारण

भारतीय हस्तशिल्प की बर्बादी के निम्नलिखित कारण गिनाए जा सकते हैं—

(1) अंग्रेजी शासन के चलते देशी रजवाड़े समाप्त हो गये जो इस उद्योग के सबसे बड़े खरीददार एवं संरक्षक थे।

(2) कम्पनी का स्वार्थ व्यापार में था। इंग्लैण्ड में भारतीय सामान पर अत्यधिक कर लगाया गया जिससे लाभ की राशि में कमी न हो। कम्पनी ने बुनकरों और दूसरे कारीगरों को कम खर्च में माल देने के लिए बाध्य किया।

(3) 1813 ई० के चार्टर ने कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त कर अंग्रेज व्यापारियों को मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। ये नये सौदागर भारत में निर्मित सामान खरीदने नहीं बल्कि इंग्लैण्ड में बने सामान बेचने और वहाँ के मिलों के लिए कच्चा माल ले जाने के लिए आए।

(4) इस अवधि में भारत के कागज उद्योग की भी क्षति हुई। ब्रिटिश शासकों ने भारत में इस्तेमाल के लिए केवल ब्रिटेन में बना कागज खरीदने का फैसला किया।

(5) ढाल, तलवार और अन्य हथियारों पर खूबसूरत दमिश्की एवं नक्काशी जैसा

Scanned with CamScanner

18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत
(आर्थिक स्थिति)

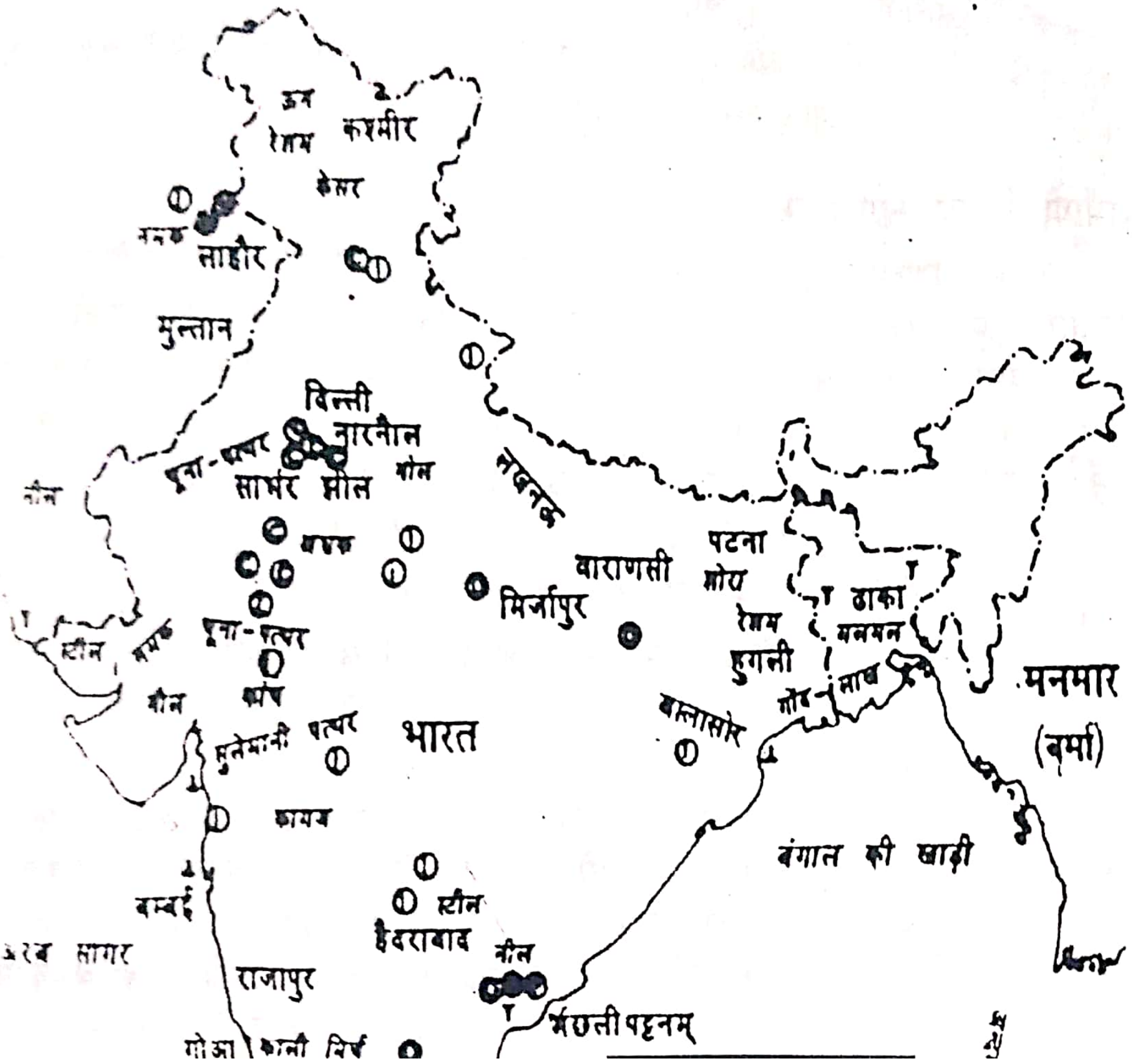

Scanned with CamScanner

काम कच्छ, सिंध और पंजाब में प्रचलित था लेकिन, अंग्रेजी शासन ने हथियारों को रखने पर पाबन्दी लगा दी जिससे यह दस्तकारी भी समाप्त हो गई।

(6) जंगलों के सरकारी संरक्षण और रेलवे के विस्तार के कारण लकड़ी के कोयले की कीमतें बढ़ीं, इससे लोहा गलाने वाले उद्योगों को काफी नुकसान हुआ।

(7) ब्रिटेन की आर्थिक नीति के कारण यहाँ के हस्तशिल्प का विनाश हुआ। एक अन्य कारण से भी ब्रिटेन ने भारत को कृषि प्रधान बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। इसे अपने उद्योगों के लिए भारत के सस्ते कच्चे माल की जरूरत थी। नतीजा यह हुआ कि खेती पर निर्भर लोगों की तादाद बढ़ती गई और गाँव के लोग लगातार गरीब होते गए।

ग्रामीण शिल्प-उद्योग का विनाश

ग्रामीण शिल्प-उद्योग प्राक् ब्रिटिश भारत का आत्म-निर्भर और ग्रामीण अर्थतंत्र का औद्योगिक पक्ष था। इससे गाँव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। गाँव में श्रम विभाजन अभी प्रारम्भिक स्थिति में था। कारीगर कुछ समय खेती में लगाते थे और किसान खासकर उनकी औरतें अपना कुछ समय सूत कातने जैसे औद्योगिक कार्यों में। ग्रामीण शिल्प उद्योग के ह्रास के निम्नलिखित कारण थे—

(1) ब्रिटेन की मशीनों से बनी सस्ती वस्तुओं की भारत में जो बाढ़ आई; वह ग्रामीण शिल्प के ह्रास का मूल कारण बनी।

(2) बाजार में मशीनों से बने सस्ते कपड़े आने से हथकरघा उद्योग पर अत्यधिक असर पड़ा। जैसे-जैसे मशीनों का उपयोग बढ़ा, वैसे-वैसे गाँव के बढ़ई की स्थिति खराब होती गई।

(3) गाँव के आर्थिक रूपान्तरण में सर्वाधिक क्षति ग्रामीण चर्मकार की हुई। पहले उसे गाँव वालों से जानवरों की लाश मिल जाया करती थी लेकिन, भारत अब विश्व मण्डली से जुड़ चुका था और चमड़े के कारखानों का विकास होने लगा। अब देशी-विदेशी उद्योगों के प्रतिनिधियों को चमड़ा बेचने में मृत पशुओं के मालिकों को फायदा था। अतः, चर्मकारों के बहुत बड़े भाग को खेतिहर मजदूर बनने को बाध्य होना पड़ा।

(4) सस्ते सिन्थेटिक रंगों के आयात से गाँवों का रंगरेज उद्योग चौपट हो गया।

(5) रोशनी के लिए केरोसीन तेल एवं क्रेसिंग मशीन आ जाने से गाँव के तेली की स्थिति बुरी हो गई।

(6) धातुओं के बर्तन आ जाने से कुम्हार द्वारा बनाई गयी चीजों का व्यापार घटा, लेकिन कुम्हार का पेशा दो कारणों से जीवित रहा। प्रथम, हमारी सांस्कृतिक आवश्यकता एवं द्वितीय, लोगों के पास धातु के सस्ते बर्तन खरीदने के पैसे भी नहीं थे।

इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये गये। इनमें सबसे प्रमुख प्रयास कांग्रेस एवं गाँधीजी ने किए। गाँधीजी ने "आल इण्डिया स्पिनर्स एसोसिशन" कायम की। गाँव में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य था। गाँधी जी ने 'आल इंडिया

... का आह्वान किया। राष्ट्रीय
... की पहली शर्त आधुनिक उद्योगों की स्थापना मानी। आधुनिक उद्योग एक ऐसा अभिकरण था जिससे भूमि पर आबादी के बढ़ते हुए दबाव को कम किया जा सकता था। **के० टी० तैलंग** और **फीरोजशाह मेहता** ने तो स्वयं 1870 ई० में बम्बई में **साबुन का कारखाना** खोलकर लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक की हैसियत से उद्योगों की स्थापना में लोगों की सहायता की।

सूती वस्त्र उद्योग

19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग का इतिहास प्रारम्भ होता है। स्थानीय पूँजी ही इस उद्योग का प्रमुख आधार बनी। **सर्वप्रथम 1818 ई० में कलकत्ता** में एक मिल की स्थापना की गई किन्तु, इस अपवाद को छोड़कर यह उद्योग बम्बई क्षेत्र में केन्द्रित रहा।

बम्बई में **पारसी कावसजी नानाभाई दामार ने 1853 ई० में पहला कारखाना** स्थापित किया। तभी से इस उद्योग का इतिहास शुरू हुआ। **जे० एन० टाटा** द्वारा 1877 ई० में **एम्प्रेस मिल नागपुर** में प्रारम्भ किये जाने के बाद वास्तविक प्रगति शुरू हुई। 1853 से 1880 ई० के प्रथम चरण में 30 कारखानों का निर्माण हुआ जिनमें 13 कारखाने पारसियों द्वारा लगाए गए। इन्हीं दिनों 1860 से 1864 ई० के अमेरिकी गृहयुद्ध के फलस्वरूप रूई के बाजार में तेजी आने से व्यापारियों के हाथों में ढ़ेर सारे पैसे आ गये और इसी समय चीन का विदेशी व्यापार भी भारतीयों के लिये खुल गया। 1880 से 1895 ई० के बीच सूती कपड़ा उद्योग में पहले की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि हुई। इन दिनों इस व्यवसाय में इतना लाभ था कि विनियोजित पूँजी 4 वर्ष में ही वापस आ जाती थी। स्वदेशी आन्दोलन को आधुनिक उद्योगों के विस्तार का आधार स्तंभ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बीच एक कड़े प्रतियोगी के रूप में जापान उठ खड़ा हुआ। **जापान** की प्रतियोगिता के कारण बम्बई के सूती धागों का व्यापार पूर्वी एशिया से समाप्त हो गया। 1914 ई० तक भारत सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में चौथे स्थान पर आ गया।

जूट या पटसन उद्योग

भारत में पहला जूट कारखाना **सेरामपुर (बंगाल)** के निकट **रिशरा** में 1855 ई० में शुरू किया गया। इस उद्योग पर पूरी तरह यूरोपियनों का आधिपत्य रहा। इसलिए, इसके विकास की अधिक सम्भावनाएं थीं। इसके लिए बंगाल में उपलब्ध पटसन अत्यन्त उपयोगी था। 19वीं शताब्दी के अन्त में, **ताराचंद घनश्याम दास सेठ** की मदद से बिड़लाओं ने कलकत्ता आकर **कच्चे जूट** के व्यापार में प्रवेश किया। **सर्वप्रथम, 1918 ई०** में एक लिमिटेड

Scanned with CamScanner

कम्पनी के रूप में बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना हुई और 1919 ई० में बिड़ला जूट कम्पनी की। 1940 ई० के बाद घनश्याम दास बिड़ला ने अंग्रेजों से अनेक कम्पनियों को खरीदकर अपना व्यवसाय बढ़ाया और तभी से जूट उद्योग में भारतीयों का प्रभुत्व स्थापित हुआ।

लोहा-इस्पात उद्योग

सर्वप्रथम, जमशेद जी टाटा के पुत्र **जे० एन० टाटा ने 1907 ई० में जमशेदपुर (बिहार)** में TISCO की स्थापना की। इसमें 1991 ई० में पिग आयरन और 1912 ई० में स्टील का उत्पादन किया जा सका। इसके बाद मैसूर में भद्रावती एवं बंगाल में भी स्टील कम्पनियाँ स्थापित की गईं। इन कारखानों से भारतीय आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति हो पाती थी। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में लोहा-इस्पात उद्योग को अधिक प्रोत्साहित नहीं किया। आधुनिक उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय समाज में दो महत्वपूर्ण वर्गों का आविर्भाव हुआ—पूँजीवादी वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग। कई नए नगरों का विकास उद्योगीकरण का परिणाम था।

वित्त व अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आयोग

आयोग/समिति का नाम	स्थापना का वर्ष	मुख्य सिफारिशें/उद्देश्य	परिणाम
अमीनी समिति	1778 ई०	इस समिति ने भू-राजस्व तथा अकाल से सम्बन्धित सिफारिशें कीं।	—
वेल्वी आयोग	—	इस आयोग ने धन-सम्पत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा-भाई नौरोजी से प्रश्न किया था।	—
निकोलसन समिति	1892 ई०	इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर रिपोर्ट पेश की।	—
दत्ता समिति	1915 ई०	इस समिति ने कीमतों के उतार-चढ़ाव पर रिपोर्ट दी।	—
मैक्लागन समिति	1915 ई०	इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर रिपोर्ट पेश की।	—
हालैण्ड समिति	1916 ई०	इस समिति ने उद्योग से सम्बन्धित सिफारिशें दी थीं।	—
औद्योगिक आयोग	1916 ई०	भारतीय उद्योगों तथा व्यापार में भारतीय वित्त प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसमें सरकार सहायता दे सके।	—

Scanned with CamScanner

आयोग/समिति का नाम	स्थापना का वर्ष	मुख्य सिफारिशें/उद्देश्य	परिणाम
मेस्टन आयोग या वित्तीय सम्बन्ध समिति	—	मेस्टन अवार्ड ने राजस्व के विभक्त मदों को त्याग करने पर बल दिया।	आय के कुछ स्रोत प्रान्तीय तथा शेष केन्द्रीय सरकार के लिए रख दिए गए।
लेटन समिति या इण्डियन स्टेट्यूटरी कमीशन	—	इस समिति ने केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच राजस्व के विभाजन के प्रश्न पर विचार प्रकट किए।	—
पील समिति या संघीय बनावट समिति	—	केन्द्र सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के बीच राजस्व के विभाजन के प्रश्न पर विचार प्रकट किए।	—
पर्सी समिति या संघीय वित्त समिति	—	केन्द्र सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के बीच राजस्व के विभाजन के प्रश्न पर विचार प्रकट किए।	—
राजस्व आयोग	1921 ई०	इसके प्रधान श्री इब्राहिम रहीमुल्ला थे। इन्होंने 1923 ई० में दी गई अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि उद्योगों को अपने प्रारम्भिक विकास की अवस्था में संरक्षण दिया जाना चाहिए।	—
लिनलिथगो आयोग	1928 ई०	इस राजकीय आयोग ने भारत में कृषि की स्थिति पर अधिकृत रूप से सुधार की अनुशंसा की।	1929 ई० में इम्पीरियल कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई।

Scanned with CamScanner